(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों पर राज सहायता का लाभ

899. **श्री राम नरेश यादव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों पर कितने करोड़ रूपये की राजसहायता प्रदान की गई और क्या सरकार ने इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि राज सहायता का लाभ वही व्यक्ति अर्थात् लघु तथा सीमान्त किसानों तक पहुंचे; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार खाद्यान्नों के लिए राजसहायता प्रदान की गई थी :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1988–89	2200
1989–90	2476 (चीनी सहित)
1990–91	2450 (चीनी सहित)

भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को खाद्यान्नों के लिए कोई सीधी राजसहायता मुहैया नहीं करती है । तथापि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि और सहकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । इस योजना के अधीन किसानों को राजसहायता मुहैया करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है । चूंकि किसानों को खाद्यान्नों के लिए सीधे कोई राजसहायता नहीं दी जाती है, इसलिए उसके बारे में कोई अध्ययन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की भर्ती

900. **श्री राम नरेश यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व दिया गया है ; यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में उनका कितना प्रतिशत है ; क्या उनके कोटे को भरने के लिये कोई विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1–4–1990 को, रेल सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का ग्रुप-वार प्रतिशत इस प्रकार है:—

ग्रुप	प्रतिशत अ० जा०	अ०ज०जा०
"ए"	11.88	3.75
"बी"	16.95	3.86
"सी"	15.33	4.68
"डी" (सफाई वालों को छोड़कर)	18.52	6.64
कुल मिलाकर	16.71	5.53

(ग्रुप "डी" में सफाई वालों को छोड़कर)

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के मामले में, ग्रुप "बी", सी" और "डी" में 15 प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में, उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण, प्रतिनिधित्व का प्रतिशत पूरा नहीं हो पाया है। एक विशेष अभियान चलाया गया था और पिछली कुछ कमी पूरी की गयी थी सेवाओं में, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के सभी प्रयास किये जाते हैं।

इस्पात की मांग

901. श्री राम नरेश यादव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग और आगामी दो वर्षों में इस्पात की मांग और पूर्ति में होने वाले लगातार अन्तर को कम करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये विभिन्न उपायों द्वारा समय-समय पर इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—

—वर्धित उत्पादन प्राप्त करने के लिये इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्र और उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

—इस्पात संयंत्रों को आदानों विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

—विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को अपनी क्षमता वार्षिक 2.5 लाख टन तक बढ़ाने की अनुमति।

—निजी क्षेत्र में भारी क्षमता वाले नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देना।

—विशेष रूप से विशिष्ट श्रेणियों की शेष मांग को आयात से पूरा किया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का पद

902. श्री राम नरेश यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का पद कब से रिक्त है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उस पद पर विधिवत नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में भारत सरकार के सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। कृषि और सहकारिता विभाग में भारत सरकार के सचिव दिनांक 5-4-90 से ही कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुये हैं। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली है। इस संबंध में आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है।

Allotment of plots in Rohini

903. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether in 1981 DDA had invited applications for allotment of residential plots under its Rohini Scheme;